

मामलों का विवरण

सिंडिकेट बैंक

वी.

एन. आर. भाट

(अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका (2020 का सिविल) 10 अक्टूबर, 2023

[हिमा कोहली और अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: पक्षकारों (प्रत्यर्थी-कर्मचारी और याचिकाकर्ता-बैंक) के बीच दिनांकित संयुक्त समझौता ज्ञापन के आधार पर मामले का निपटारा किया गया था, हालांकि, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी-कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के विकल्प का उपयोग करने की अनुमति दी और याचिकाकर्ता-बैंक को उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

सेवा कानून-प्रतिवादी-कर्मचारी को याचिकाकर्ता-बैंक द्वारा खारिज कर दिया गया था-उच्च न्यायालय के समक्ष, पक्षकार दिनांकित एक संयुक्त ज्ञापन के संदर्भ में एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचे, जिसमें याचिकाकर्ता-बैंक के तहत प्रतिवादी-कर्मचारी पर लगाए गए सेवा से बर्खास्तगी के जुर्माने को चार चरणों तक वेतन के समय पैमाने में कमी के जुर्माने के साथ प्रतिस्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई, लेकिन उसके सेवानिवृत्ति लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना-इसके अलावा, प्रतिवादी-कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के विकल्प का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी गई थी और याचिकाकर्ता-बैंक को उचित आदेशों पर विचार करने और पारित करने के लिए आगे निर्देश दिया गया था-प्रतिवादी-कर्मचारी, याचिकाकर्ता-बैंक को दी गई स्वतंत्रता से व्यथित अपील:

आयोजित किया गया: याचिकाकर्ता-बैंक की प्रस्तुति ने सरल कारण से स्वीकार किया कि भले ही प्रत्यर्थी-कर्मचारी की बर्खास्तगी पर नियुक्ता-कर्मचारी का संबंध समाप्त हो गया था, एक बार जब अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिनांकित आदेश द्वारा बरकरार रखा गया था, तो उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित निर्णय के आधार पर खारिज कर दिया गया था, याचिकाकर्ता-बैंक और प्रत्यर्थी-कर्मचारी के बीच नाभि बहाल हो गई थी और प्रत्यर्थी-कर्मचारी के लिए दिनांकित परिपत्र 16.04.2010 के संदर्भ में विकल्प (पेंशन) का उपयोग करने का पर्याप्त अवसर था, जो वह 476 करने में विफल रहा।

475

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

– बस छूट जाने के बाद, प्रतिवादी-कर्मचारी पेंशन के किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकता था, वह भी याचिकाकर्ता-बैंक के साथ समझौते के संयुक्त ज्ञापन में प्रवेश करने के बाद-जहां तक संयुक्त ज्ञापन के अनुसार राशि जारी करने का संबंध है, इस अदालत ने पार्टियों के बीच संयुक्त ज्ञापन को लागू करने की अनुमति दी-याचिकाकर्ता-बैंक ने प्रतिवादी-कर्मचारी को भुगतान की जाने वाली राशि को समझौते के ज्ञापन के संदर्भ में जारी नहीं किया और यह कि उक्त राशि हाल ही में 30.09.2023 पर जारी की गई थी-इसलिए, प्रतिवादी-कर्मचारी को दिनांकित 17.06.2019 के संदर्भ में उसे देय निपटान बकाया को अवैध रूप से रोकने के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए।[पैरा 7,9,10]

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

असाधारण अपील न्यायनिर्णय:2020 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.7277।

2005 के डब्ल्यू. ए. No.3255 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

पुनीत तनेजा, मनमोहन सिंह नरुआ, अमित यादव, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

आयुष नेगी, सुश्री विशाखा उपाध्याय, शिखर चंदा, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

आदेश

1. याचिकाकर्ता-बैंक उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अंतर-न्यायालय अपील 1 में पारित 17 जून, 2019 के एक आदेश से व्यथित है।

1 2005 477 की लिखित अपील No.3255

सिंडिकेट बैंक बनाम एन. आर. भाट 478

जिसके तहत, पक्षकारों के नेतृत्व में 17 जून, 2019 के संयुक्त ज्ञापन को रिकॉर्ड में लेते हुए, प्रतिवादी-कर्मचारी के विद्वान वकील द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखते हुए कि वह याचिकाकर्ता-बैंक को पेंशन का विकल्प चुनने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करेगा।प्रत्यर्थी-कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के विकल्प का उपयोग करने और उसके बाद आठ सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित करने के लिए याचिकाकर्ता-बैंक से लिखित अनुरोध करने की अनुमति दी गई थी।2. पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर ध्यान देने से पहले, प्रासंगिक तथ्यों का एक संक्षिप्त संदर्भ आवश्यक है:

3. प्रतिवादी-कर्मचारी 31 मार्च, 1969 को एक आधिकारिक प्रशिक्षु के रूप में याचिकाकर्ता-बैंक की सेवाओं में शामिल हुए। परीक्षा पूरा होने पर, उन्हें 3 अक्टूबर, 1969 को परीक्षाधीन कनिष्ठ अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। 6 अगस्त, 1982 को प्रतिवादी-कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही के विचार में निलंबित कर दिया गया था। अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त होने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने 3 मार्च, 1997 को प्रतिवादी-कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 6 अप्रैल, 1997 के आदेश के माध्यम से बरकरार रखा गया है। उपरोक्त आदेशों से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी-कर्मचारी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका 2 को प्राथमिकता दी। 23 जून, 2005 के आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित दो आदेशों को रद्द कर दिया और मामले को पुनर्विचार के लिए याचिकाकर्ता-बैंक को वापस भेज दिया गया।

4. उक्त आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अंतर-न्यायालय अपील 1 को प्राथमिकता दी। रिट अपील के लंबित रहने के दौरान, पक्षकार 17 जून, 2019 के एक संयुक्त ज्ञापन के संदर्भ में एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचे, जिसमें याचिकाकर्ता-बैंक ने प्रतिवादी-कर्मचारी पर लगाए गए सेवा से बर्खास्तगी के जुर्माने को चार चरणों तक वेतन के समय पैमाने में कमी के जुर्माने के साथ बदलने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन उसके सेवानिवृत्ति लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। यह उपरोक्त संयुक्त ज्ञापन को अभिलिखित करने के क्रम में था कि प्रतिवादी-कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के विकल्प का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए और याचिकाकर्ता-बैंक को इसके बाद आठ सप्ताह के भीतर इस तरह के अभ्यावेदन पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने के निर्देश के साथ विवादित आदेश पारित किया गया।

2 लेखन याचिका No.20386/1997

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

5. प्रत्यर्थी-कर्मचारी को दी गई उपरोक्त स्वतंत्रता से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता-बैंक ने वर्तमान याचिका का नेतृत्व किया है जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय को प्रत्यर्थी-कर्मचारी को पेंशन लाभ के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पूरा मामला पक्षों के बीच 17 जून, 2019 के संयुक्त समझौता ज्ञापन के आधार पर सुलझा लिया गया था; कि याचिकाकर्ता-बैंक के साथ समझौते की कोई और गुंजाइश नहीं थी और प्रत्यर्थी-कर्मचारी को वर्ष 1995 में पेंशन योजना का विकल्प चुनने का अवसर मिला था जब सिंडिकेट बैंक कर्मचारी (पेंशन विनियम) को पहली बार अधिसूचित किया गया था और उस समय वह बैंक का कर्मचारी था, लेकिन ऐसा करने में विफल रहा था।

6. याचिकाकर्ता-बैंक के विद्वान वकील ने आगे इस न्यायालय का ध्यान 16 सितंबर, 2010 के परिपत्र की ओर आकर्षित किया, जिसके तहत प्रतिवादी-कर्मचारी के नेतृत्व में जवाबी हलफनामा (अनुलग्नक ए) था, जिसके तहत उन कर्मचारियों को एक और अवसर दिया गया था जिन्होंने पहले पेंशन का विकल्प नहीं चुना था, ताकि वे उक्त परिपत्र के संदर्भ में ऐसा कर सकें। यह कहा गया है कि शीर्षक परिपत्र के संदर्भ में प्रतिवादी-कर्मचारी के लिए उक्त विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद, वह इसका उपयोग करने में विफल रहा था और इसलिए, वर्ष 2019 की तरह पेंशन के लिए अपने विकल्प का उपयोग करने के मुद्दे को उठाने से रोक दिया गया है।

7. हम याचिकाकर्ता-बैंक के विद्वान वकील द्वारा इस साधारण कारण से की गई दलील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं कि भले ही 3 मार्च, 1997 को प्रतिवादी-कर्मचारी की बर्खास्तगी पर नियोक्ता-कर्मचारी का संबंध समाप्त हो गया था, एक बार जब अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश और 6 अप्रैल, 1997 के आदेश के माध्यम से अपीलीय प्राधिकरण द्वारा बरकरार रखा गया था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा 23 जून, 2005 के फैसले के आधार पर दरकिनार कर दिया गया था, याचिकाकर्ता-बैंक और प्रतिवादी-कर्मचारी के बीच गर्भनाल बहाल हो गई थी और प्रतिवादी-कर्मचारी के लिए 16 अप्रैल, 2010 के परिपत्र के संदर्भ में विकल्प का उपयोग करने का पर्याप्त अवसर था, जो वह करने में विफल रहा था। बस छूटने के बाद, प्रतिवादी-कर्मचारी पेंशन के किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकता था, वह भी याचिकाकर्ता-बैंक के साथ समझौते के संयुक्त ज्ञापन में प्रवेश करने के बाद। 8. इसलिए, हमारी राय है कि वर्ष 2019 में इस तरह के विलंबित चरण में प्रतिवादी-कर्मचारी द्वारा इस तरह के किसी भी विकल्प का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

सिंडिकेट बैंक बनाम एन. आर. भाट

479

9. इस स्तर पर, प्रत्यर्थी-कर्मचारी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि 30 जून, 2020 को वर्तमान याचिका में नोटिस जारी करते समय, इस न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि पैरा 6 में डिवीजन बेंच के निर्देशों को लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि, उच्च न्यायालय में 17 जून, 2019 के संयुक्त ज्ञापन को लागू करने की अनुमति दी गई थी। यह कहा गया है कि उक्त आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता-बैंक ने निपटान ज्ञापन के संदर्भ में प्रतिवादी-कर्मचारी को देय राशि जारी नहीं की और उक्त राशि हाल ही में 30 सितंबर, 2023 को जारी की गई थी। इसलिए, उनका कहना है कि प्रतिवादी-कर्मचारी को 17 जून, 2019 के संयुक्त ज्ञापन के संदर्भ में उसे देय निपटान बकाया को अवैध रूप से रोकने के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए।

10. हम प्रत्यर्थी-कर्मचारी के लिए विद्वान वकील द्वारा किए गए उपरोक्त प्रस्तुतिकरण में सार रखते हैं। याचिकाकर्ता-बैंक को पहली तारीख को ही स्पष्ट कर दिया गया था कि संयुक्त ज्ञापन को लागू किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता-बैंक को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए, इसे लागू नहीं किया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता-बैंक को प्रत्यर्थी-कर्मचारी को ब्याज का भुगतान करके पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया जाता है, जो हमारी राय में, एक एफ. डी. आर. पर ब्याज की सामान्य दर से अधिक होना चाहिए जिसे याचिकाकर्ता-बैंक बड़े पैमाने पर जनता को देता है। इस

तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह सेवानिवृत्ति लाभ को रोकने से संबंधित एक मुद्दा है, याचिकाकर्ता-बैंक को प्रतिवादी-कर्मचारी को 1 जुलाई, 2019 से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देना उचित समझा जाता है, जब तक कि उक्त राशि प्रतिवादी-कर्मचारी के पक्ष में जारी नहीं की जाती है। ब्याज घटक का भुगतान आज से चार सप्ताह के भीतर किया जाएगा, ऐसा न करने पर इसे 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया जाएगा।

11. अपील के लिए विशेष अनुमति की याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों पर किया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिका का निपटारा किया गया।

अंकित ज्ञान